LOK SABHA

Saturday, March 22, 1969/Chaitra 1, 1891 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MR. SPEAKER *In the Chair*]

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Reported decision of the Congress Party to consult the Attorney-General on Madhya Pradesh High Court's order in respect of Shri D. P. Mishra

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (बलरामपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर गृह-कार्य मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :-

> "मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा श्री द्वारिका प्रसाद मिश्र के सम्बन्ध में दिये गये आदेशों के कानूनी आशयों के बारे में महान्यायवादी से परामर्श लेने का कांग्रेस दल का कथित निश्चय "।

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI Y. B. CHAVAN) : The Central Government have taken steps to obtain the advice of the Attorney-General on the Constitutional and legal issues involved in the question whether, in view of the orders passed by the High Court of Madhya Pradesh in election case involving Shri D.P. Mishra, the Governor, Madhya Pradesh, could invite Shri D. P. Mishra, the present Leader of the Congress Party in Madhya Pradsh Legislative Assembly to form the Ministry. The Governor has also wished to obtain the opinion of the Attorney-General on this matter. There is no question of the Congress Party seeking the advice of the Attorney-General.

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : झूठ। गलत। बड़े चतुर आदमी हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मुझे गृह मंत्री का वक्तव्य सुन कर आश्चर्य भी हुआ और खेद भी हुआ। 20 तारीख को कांग्रेस पार्लियामेंटरी बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें यह निश्चय किया गया कि पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र के सम्बन्ध में निर्णय करने से पहले एटार्नी जेनरल की राय ली जाये। यह निर्णय कांग्रेस अध्यक्ष ने समाचारपत्रों को बताया। मैं इंडियन एक्सप्रेस को उद्धृत करना चाहता हूं :

> "The Congress President, Mr. S. Nijalinagappa, told newsmen that the Board wanted to get the Attorney-General's opinion about Mr. Mishra."

इस आशय के समाचार और समाचारपत्रों में भी प्रकाशित हुए। उन सब को दोहराने की आवश्यकता नहीं है। अखबारों में यह खबर प्रकाशित होने पर हम आपके पास गये और हम ने कहा कि हम इस कार्यवाही के औचित्य को चुनौती देना चाहते हैं। पंडित द्वारिका प्रसाद

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

मिश्र के सम्बन्ध में कांग्रेस पार्लियामेंटरी बोर्ड कुछ भी फैसला करे, लेकिन वह भारत के एटार्नी जेनेरल की राय नहीं ले सकता है। एटार्नी जेनेरल किसी पार्टी को सलाह देने के लिए नहीं बने हैं। वह भारत सरकार और पार्लियामेंट को सलाह दे सकते हैं। जब यह मामला उठाया गया, तब गृह मंत्री ने यह फैसला किया कि पार्लियामेंटरी बोर्ड के निर्णय ने कांग्रेस पार्टी को संकट में डाल दिया है और इसलिए अब भारत सरकार को एटार्नी जेनेरल की राय लेनी चाहिए।

मैं यह जानना चाहता हूं कि एटार्नी जेनेरल की राय भारत सरकार ले, यह निर्णय कब किया गया, किस तारीख को किया गया, कितने बजे किया गया। क्या यह निर्णय कांग्रेस पार्लियामेंटरी बोर्ड के 20 तारीख के निर्णय से पहले किया गया? और अगर यह निर्णय उससे पहले किया गया, तो फिर इस सम्बन्ध में सदन को विश्वास में क्यों नहीं लिया गया? इस सम्बन्ध में हम लोगों ने जो अल्प-सूचना प्रश्न भेजे थे और जो ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचना दी थी, उन को गृह मंत्री ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वह समझते थे कि कांग्रेस पार्लियामेंटरी बोर्ड ने उस समय तक इस बारे में फैसला नहीं किया है। लेकिन अब गृह मंत्री कहते हैं कि भारत सरकार के निर्णय के आधार पर एटार्नी जेनेरल से पूछा जा रहा है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि वह निर्णय कब किया गया।

दूसरा प्रश्न यह है कि पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र के सम्बन्ध में भारत सरकार एटार्नी जेनेरल की राय ले, इसका क्या औचित्य है। पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र भारत के एक नागरिक हैं।

एक माननीय सदस्य : एक मामूली नागरिक हैं।

एक और माननीय सदस्य : एक डिसक्वालिफाइड नागरिक हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उनका चुनाव रद्द हो गया। चुनाव में भ्रष्ट तरीके अपनाने के कारण मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय ने उन का चुनाव रद्द कर दिया। इस मामले में केंद्रीय सरकार तस्वीर में कहां आती है? वह मुख्य मंत्री बनें या न बनें, मध्य प्रदेश के राज्यपाल उन्हें सरकार बनाने के लिए बुलायें या न बुलायें, इसमें केन्द्रीय सरकार नहीं आती है। अगर हाई कोर्ट का फैसला किसी और नागरिक के खिलाफ जायेगा, तो क्या केन्द्रीय सरकार उस के बारे में भी इस तरह की राय लेने के लिए तैयार होगी? क्या केन्द्रीय सरकार का फैसला गवर्नर के निर्णय पर आधारित है? मैं कहना चाहता हूँ कि केन्द्रीय सरकार अपनी पार्टी के एक व्यक्ति के सम्बन्ध में निर्णय लेने के लिए एटार्नी जेनेरल के पद का दुरुपयोग कर रही है। इस तरह उस पद का दुरुपयोग करने का कोई कारण नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के यह फैसला करने का आधार और औचित्य क्या है। क्या भविष्य में भारत के किसी भी नागरिक के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार इसी तरह एटार्नी जेनेरल की राय लेने के लिए तैयार होगी? अगर मेरी पार्टी के किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में यह सवाल आये कि वह मुख्य मंत्री बने या न बने, तो क्या हम भारत सरकार के जरिये एटार्नी जेनेरल की सलाह ले सकेंगे?

प्रश्न केवल कानूनी नहीं है। प्रश्न सांविधानिक औचित्य, कांस्टीट्यूशनल प्रोप्रायटी, और राजनैतिक नैतिकता, पोलीटिकल मोरैलिटी, का भी है। मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने भ्रष्ट तरीके अपनाने के आधार पर एक व्यक्ति का चुनाव अवैध घोषित कर दिया है। हाईकोर्ट ने जो स्टे आर्डर दिया है, उसमें कहा गया है कि पंडित

द्वारिका प्रसाद मिश्र विधान सभा में बैठ सकते हैं, लेकिन वह कार्यवाही में भाग नहीं ले सकते हैं. वोट नहीं दे सकते हैं। क्या हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ प्रयुक्त करने के लिए भारत सरकार एटार्नी जेनेरल की राय लेना चाहती है ?

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बतूल) : क्या इसका निर्णय हम लोग करेंगे ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, जब गृह मंत्री ने यह मान लिया है कि एटार्नी जेनेरल की राय ली जा रही है, तो मैं आपके सामने अपनी प्रार्थना दोहराना चाहता हूँ कि इस सवाल पर सदन में बहस होनी चाहिये और एटार्नी जेनेरल को सदन के सामने बुलाया जाना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 88 के अनुसार एटार्नी जेनेरल सदन में आ सकते हैं, अपने विचारों से सदन को अवगत कर सकते हैं और सदस्य उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं। मध्य प्रदेश के गवर्नर को भी एटार्नी जेनेरल की राय लेने का अधिकार नहीं है। वह एडवाकेट जेनरल की राय ले सकते हैं, एटार्नी जेनेरल की राय नहीं। अगर एटार्नी जेनरल की राय ली जानी है, तो केन्द्रीय सरकार के द्वारा ली जानी चाहिए। मेरी प्रार्थना है कि आप एटार्नी जेनेरल को सदन में बुलाने की हमारी प्रार्थना को स्वीकार करें।

MR. SPEAKER : Before the hon. Minister answers, I want to say something. Shri Vajpayee also wrote to me about that. There are four ways of calling the Attorney-General. Attorney-General can come if he wants to. The Government can call him if they wants some clarification.

SHRI NATH PAI (Rajapur) : We want. (*Interruptions*).

MR. SPEAKER : I said there are four ways. I have mentioned only two Why do you shut me out ? The other way is, if the House wants, they may call him. (*Interruptions*) I say, if the House wants, they may call him. When I say, House, no shouting should take place. One is, he can himself come; the second, the Government can call him; and the third, the House can call him. There is a fourth way. I am coming to the fourth possibility. If the Speaker is in doubt about some legal aspet he can call. But now the Speaker is not involved in this I am sitting here as Speaker now. If the Speaker is involved in any legal point where he has to give a ruling or something where he is in doubt or where he has to give some sort of judgment naturally this can be done. But here there is no point on which I am asked to give any ruling here.

There is a controversy about Attorney-General being called by the Congress party which we are discussing now.. (*Interruptions*) Hon. Members should hear me now..

SHRI PILOO MODY (GODHRA) : We shall keep quitet if you just phone him up.

MR. SPEAKER : The point that is now before the House is abount the Congress Party or the Congress President asking for the opinion of the Attorney-General The other things such as whether Shri D. P. Mishra will be Chief Minister or not are not before the House at all now. We are not discussing that question now. The question is whether the Congress Party can call the Attorney-General to give his opinion. That is the point now before the House. Therefore the question of my calling the Attorney General does not arise. If the House wants, it can call him at any time it likes.

SHRI S. M. BENERJEE (Kanpur) : Then I move that the Attorney-General be called to this House.

SHRI SHEO NARAIN (Basti) : If the House wants, and not if the Opposition wants.

MR. SPEAKER : There is no motion now before me. When it comes we shall consider it.

SHRI CHENGALRAYA NAIDU (Chittoor) : On a point of order. Anybody has got a right to consult the Attorney-General in his private capacity. There is

[Shri Chengalraya Naidu]

no bar to the Attorney-General being called to work for anybody. The Congress Party has got a right to consult him.

MR. SPEAKER : There is no point of order. Now, the Home Minister may reply.

SHRI Y. B. CHAVAN : I really do not understand the controversy in this matter, because when the Governor himself expressed a desire to consult the Attorney-General ..

SHRI KNAWAR LAL GUPTA (Delhi Sadar) : Why not the Advocate-General?..

SHRI Y. B. CHAVAN : I can understand his dislike of Shri D. P. Mishra. It is his right to do so. But when an intricate constitutional and legal issue is raised, shall we not as a House, and shall I not as an Indian citizen expect that he should consult a proper legal authority ? What is wrong about it ? The Attorney-General is certainly entitled to give his opinion, and the Government of India are entitled to get the opinion of the Attorney-General. It is wrong to say that the Governor has to consult only the Advocate-General, and it is not proper for him to get the opinion of the Attorney-General. The question has been asked why the Government of India decided to consult the Attorney-General. A situation was developing in the State, where a constitutional issue was likely to be raised.

AN HON. MEMBER : Mr. Shukla is there.

SHRI Y. B CHAVAN : The Governer has, therefore, expressed a desire to consult the Attorney-General. And this House also expects me to express my opinion at any time So, is it not right for me to get myself armed with the opinion of the Attorney-General in this matter ? What is wrong about it ? I think unnecessarily a controversy is being created. I think hon. Members will also be satisfied that whatever decision the Governor takes or we take in this matter is based on a proper constitutional and legal appreciation of the position by the Attorney-General; it is good to be advised by a competent constitutional authority.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया गया। मैं जानना चाहता हूं कि एटार्नी जनरल की राय लेने का फैसला कब किया गया, किस तारीख को ? क्या यह सच है कि कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड के फैसले के बाद किया गया ?

श्री यशवंतराव चव्हाण : नहीं, मैं आप से कहना चाहूंगा, आप मेरे पर भरोसा करना चाहें तो करें, लेकिन आप संशय से काम करना चाहें तो आप अपने मालिक हैं, जो चाहें करें।

I discussed this matter with the Law Minister on the 19th instant. I do not remember exactly when the parliamentary board's meeting took place. I may tell my hon. friend this: if he wants to believe it he may believe it, otherwise not. In the parliamentary board I did say that in these matters Government would like to be guided by the Attorney General, and naturally when the Governor also expressed a desire to consult the Attorney-General, the Attorney-General came to be mentioned in the parliament board; he came to be mentioned only in this context.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री कह रहे हैं कि उन्होंने डिस्कस किया। मैं डिस्कशन की बात नहीं कर रहा हूं। गवर्नमेंट आफ इंडिया का फैसला है या नहीं कि एटार्नी जनरल की राय ली जाय ? किसी प्राइवेट मीटिंग में डिस्कशन से मतलब नहीं है।

SHRI Y. B. CHAVAN : I told him that I discussed it with the Law Minister on the 19th instant.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : किस तारीख का फैसला है ? फाइल पर कोई नोटिंग है ?

MR. SPEAKER : He must have taken the decision on the 19th perhaps.

SHRI S. KANDAPPAN (Mettur) : Why did he not take the House into confidence ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक और प्रश्न पूछा था कि श्री डी० पी० मिश्रा के मामले में जो कांस्टीट्यूशनल प्रोप्राइटी, और पोलिटिकल मोरेलिटी का पहलू है क्या गृह मंत्रालय ने या केन्द्रीय सरकार ने इस पर भी विचार किया है ? क्या एक भ्रष्ट आदमी को मुख्य मत्री बनाने पर केन्द्रीय सर–कार तुली हुई है ?

SHRI Y. B. CHAVAN : I do not understand this. Is he afraid that the Attorney-General .. *(Interruptions)*

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : प्वाइंट आफ आर्डर। अटल जी ने कहा है कि एक भ्रष्ट आदमी को ......

श्री रबि राय (पुरी) : हाई कोर्ट ने कहा है।

MR. SPEAKER: If it is a point of order, I can allow him. But if he wants to put a question on the calling-attention-notice, then I cannot allow anybody else.

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर यह है कि अगर हुकम चंद कछवाय ऐसी कोई बात कहें तो मेरी समझ में आती है, बाबूराव पटेल ने उनको टार्जन कहा है अपने अखबार में। वह नहीं जानते हैं टार्जन कहना कितना अपमानजनक है ? अटल जी के लिए हम लोगों को सबको एक इज्जत है। वह एक सयमित रूप से यहां आपके सामने बात रखते हैं। आपने कहा कि एक भ्रष्ट आदमी को वहां का हम मुख्य मंत्री नहीं बनाना चाहते। वह भ्रष्ट हैं या नहीं हैं इस बात का फैसला अभी सुप्रीम कोर्ट से होने वाला है।... (व्यवधान)

श्री हुकम चन्द कछवाय : हो गया है...

एक माननीय सदस्य : जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं होता तब तक वह भ्रष्ट हैं।...(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि अटल जी ने जो उन्हें भ्रष्ट करके कहा है उसको आप एक्सपंज कर दीजिए।

MR. SPEAKER : Will hon. Members kindly sit down now ? I thought the word *'bhrashtachar'* was used for.. *(Interruptions)*

May I request all hon. Members to resume their seats ? Shri N. K. P. Salve wanted my ruling on the point he had raised...

SHRI NARENDRA KUMAR SALVE : I want your ruling.

MR. SPEAKER : I am giving my ruling. I thought that the word *'bhrashtachar'* meant corruption or something like that. I do not know so much of Hindi...

श्री शिवनारायण : भ्रष्ट से मतलब करप्ट से है।

MR. SPEAKER : I do not want to learn Hindi at this stage. I would like to learn Hindi from him later on, but not while sitting in the Chair. I thought that the word *'brashtachar'* meant corrupt practices.

SHRI RANDHIR SINGH (Rohtak) : He has said *'brasht'*. He said 'corrupt person'.

MR. SPEAKER : I think he said 'corrupt practices'.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI P. C. SETHI) : He said corrupt, not 'corrupt practices'.

SHRI RANDHIR SINGH : He said 'corrupt person'.

MR. SPEAKER : I thought that he was referring to the High Court judgement.

SHRI NARENDRA KUMAR SALVE : The High Court has not said that he is corrupt. 'Corrupt practice' is something different from 'corrupt'.

MR. SPEAKER : I shall look into that then. I am not able to make that subtle distinction now about the language and what actually it means.

SHRI RANDHIR SINGH: It is pending in appeal. *(Interruptions)*

श्री शिवनारायण : सर, यह हाउस नहीं चलेगा। अगर यह हल्ला करते हैं तो इस हाउस की वर्किंग नहीं होने पायेगी। अटल बिहारी को हम बोलने नहीं देंगे...(व्यवधान)

MR. SPEAKER : I am not able to judge what it implies. I know a little Hindi, but I am not such an expert in Hindi. I shall have to see that before his request for expunction is looked into. *(Interruptions)* When I am on my legs, I do not want to hear any further arguments.

I thought that the word *'brashtachar'* was being used every day for 'corrupt practices'; his elections has been set aside for corrupt practices...

SHRI PILOO MODY : What is wrong with calling him corrupt ?

MR. SPEAKER : The word *'bhrashtachar'*. . . *(Interruptions)* If hon. Members do not want to hear me, I do not want to speak. Unless the House gives me a hearing I am not going to speak. If every minute I am going to be interrupted like this, then I am not going to speak. The House should hear me when I am on my legs. On the question of corrupt practice, the High Court gives a judgement and then the elections are set aside.

I remember that the election of Dr. Chenna Reddy was set aside, and he resigned within 24 hours of the High Court judegment, not the Supreme Court's judgement but the High Court judegment. I had also known cases there after the court judegment normally the people resigned. That is a different matter. I am not interested in whether one resigns or one does not resign. Here is a case where a Minister resigned immediately after the High Court judgement; he was hoping to come back after the Supreme Court judgement, but still he resigned after the High Court judegment.

A regards the difference between the words *'bhrasht'* and *'bhrashtachar'*, I am not very clear, and I shall slowly try to study it, and then only try to make up my mind; I am not able to say it just now. Let the hon Member please leave it at that. If as the hon. Member says what it means is something else than what is contained in the High Court judgement; then I shall see and the hon. Member has a point.

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : उन्होंने भ्रष्ट कहा है.......

MR. SPEAKER : Let him not spoil the case. I have already made the point.

SHRI PILOO MODY : What is wrong with that ?

SHRI NATH PAI : Why not call a spade a spade ?

MR. SPEAKER : To say 'corrupt practice' and to call a man corrupt are slightly different ..

SHRI PILOO MODY : I want to know what is wrong with it. I would like to seek a clarification from you. I do not know why we are discussing the matter at all. I do not see what is wrong in calling him corrupt. So, if you like, you better give your ruling on that. *(Interruptions)*

MR. SPEAKER : Let us not go into those controversies now.

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : अध्यक्ष महोदय, संविधान की धारा 76(2) के तहत एटोर्नी जेनरल के जो कर्त्तव्य हैं उनका जिक्र करते हुए कहा गया है कि राष्ट्रपति जिन मामलों के बारे में कहेंगे, उन मामलों के बारे में केन्द्र सरकार एटार्नी-जेनरल से सलाह ले सकती है। लेकिन जहां केन्द्र के हितों का और दूसरों के हितों का टकराव होगा–कानून मंत्री भी इस बात को मानेंगे–एटार्नी जेनरल कोई सलाह नहीं दे सकता।

यह बात तो सलाह के बारे में हुई, लेकिन मेरा प्रश्न दूसरा है–मैं कानूनी बारीकी में नहीं जाना चाहता, उसके बारे में एटार्नी–जनरल सदन के सामने आकर कहें, वह बात दूसरी है, लेकिन इसमें उचित क्या है और अनुचित क्या है-इसका सवाल आ जाता है। अध्यक्ष महोदय, स्वयं आपने एक अच्छी परिपाटी इस सम्बन्ध में डाली है और आप हमेशा मुझको याद भी देते हैं कि आपने अदालत के फैसले के बाद तुरन्त अपना इस्तीफा दिया था और मैंने आपको एक पत्र भी लिखा था। आपने कहा था कि आपके मन में जो सन्देह था, वैसा नहीं हुआ, आपने अपना इस्तीफा वापस नहीं लिया। इसके अलावा चेन्ना रेड्डी का मामला आया, उनको भी हटना पड़ा, इतना ही नहीं, जब राजा रामगढ़ के बारे में मैंने यह तथ्य सदन के सामने रखा कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने उनके बारे में आलोचना की है, श्री हनुमतैया और दूसरे लोगों ने भी मेरी बात का समर्थन किया, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में भी इसके बारे में हल्ला हुआ, सुब्रह्मण्य साहब को इस्तीफा देना पड़ा। यह सार्वजनिक सवाल है, कांग्रेस पार्टी का सवाल नहीं है। अन्त में मैंने सुना है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने भी इस बात को कुबूल किया है कि राजा को हटाना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, ये तीन मसले हम लोगों के सामने है तो क्या वजह है कि सरकार एटार्नी-जनरल की राय लेने और संवैधानिक आपत्तियों के चपले में जाने के बजाय सीधा निर्णय नहीं करती है। औचित्य को लेकर जिसके बारे में हाइकोर्ट ने कहा है कि उन्होंने भ्रष्ट व्यवहार का जुर्म किया हैं—भ्रष्ट का मतलब जो भ्रष्ट व्यवहार करता है वह भ्रष्ट है–करप्ट प्रेक्टिसेज तो ऐसा जिसके बारे में कहा गया है और हाइकोर्ट के निर्णय के खिलाफ अभी तक सुप्रीम कोर्ट में कोई अपील भी नहीं है, अपील दायर भी नहीं की गई है, सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्टे-आर्डर भी नहीं दिया हैं-इसलिये अन्तिम निर्णय इस वक्त हाइकोर्ट का है। हाइकोर्ट ने इनको इजाजत दी है कि 60 दिन में एक दिन वह विधान सभा में जा सकते हैं ताकि उनकी सदस्यता खत्म न हो, क्योंकि हमारे यहां भी और वहां की विधान सभा में ऐसा नियम है कि 60 दिन तक यदि कोई सदस्य न जाय तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाती है ...

SHRI NARENDRA KUMAR SALVE : A correction-he can go any day.

MR. SPEAKER : That is accepted.

SHRI S. M. BANERJEE : He is shameless.

श्री मधु लिमये : हमको तो 60 दिन वाली बात का पता चला है। 60 दिन तक अगर कोई सदस्य गैर हाजिर रहे तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाती है। वह न कार्यवाही में हिस्सा ले सकते हैं, और न बोल सकते हैं और न वोट दे सकते हैं, ऐसी हालत में क्या सरकार इस बात पर गौर फरमायेगी–मैं तो यह भी मानता हूँ कि जो सदस्य भी नहीं है उसको मुख्य मंत्री कैसे बनाया जा सकता हैं–164 (4) के अन्तर्गत-लेकिन ये सदस्य हैं और इनकी सदस्यता को बनाये रखने के लिये स्टे-आर्डर दिया गया है, लेकिन इन्हें डिस्क्वालिफाई भी किया है—ऐसी हालत में एक अच्छी परिपाटी डालने के लिये क्या गृह मंत्री इस सदन में इस बात की घोषणा करेंगे कि श्री संजीवरेड्डी, चेन्ना रेड्डी और राजा रामगढ़....

SHRI NATH PAI : Do not group all of them together. Leave the Speaker out.

MR. SPEAKER : I will have to be left out once for all.

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, मैं एक अच्छी परिपाटी की चर्चा कर रहा हूं, इसमें कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिये–मैंने तो पहले ही कहा है कि आपने एक अच्छी परिपाटी डाली है ...

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : लेकिन मिश्र जी कहां डाल रहे हैं ?

श्री मधु लिमये : इसीलिये मैं कह रहा हूं कि क्या गृह मंत्री घोषणा करेंगे, इस सदन को आश्वासन देंगे कि किसी भी हालत में जब तक सुप्रीम कोर्ट में उनको पूर्णतया निर्दोष साबित नहीं किया जाता, श्री डी० पी० मिश्र को मुख्य मंत्री बनाने की बात हम सोचेंगे भी नहीं। इससे सारा मामला खत्म हो जायेगा।

SHRI Y. B. CHAVAN : I am supposed to give clarification, not assurance, at this stage.

MR. SPEAKER : The call attention is about seeking the opinion of the Attorney-General. Now he is asking whether Shri D. P. Mishra will be allowed or not. That is a separate questeon.

श्री मधु लिमये : यह इसीमें से आता है, अध्यक्ष महोदय, तारांकित तथा अल्प सूचना प्रश्न पर जो सप्लीमेन्ट्रीज पूछे जाते हैं, उसी तरह यह उससे सम्बन्धित है। इस का जवाब इनको देना चाहिये, वर्ना चर्चा का कोई मतलब नहीं रह जाता।

MR. SPEAKER : Even if he wants to, he has to consult the Attorney-General and take legal opinion and then only can answer this question.

श्री मधु लिमये : मैंने औचित्य का, प्रोप्राइटी का सवाल उठाया है। यह राजनीतिक मूल्यों का सवाल है। मैं कानूनी बातों में नहीं जा रहा हूं, संविधान में नहीं जा रहा हूं–आप इतना सदन को आश्वासन दे दीजिये कि औचित्य का ख्याल रखते हुए मिश्र जी को मुख्य मन्त्री नहीं बनायेंगे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप यह कहिये कि औचित्य का ख्याल किया जायेगा या नहीं ?

श्री रणधीर सिंह : इसका होम मिनिस्टर से क्या ताल्लुक है ?

MR. SPEAKER : Shri Shiva Chandra Jha.

श्री शिवचन्द्र झा (मधुबनी) : अध्यक्ष महोदय,....

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, आप यह निर्णय नहीं दे रहे हैं, इससे सारे सप्लीमेन्ट्रीज हमेशा के लिये खत्म हो जायेंगे। मैं सार्वजनिक हित में इसका जवाब नहीं देता–ऐसा वह कह सकते हैं। आप कुछ परिपाटी तो रखिये।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : गृह मंत्री ने जो उत्तर दिया है, उसमें उन्होंने स्वीकारा है कि वह स्वयं संवैधानिक पहलू के बारे में राय लेने जा रहे हैं। क्या मैं गृह मंत्री से पूछ सकता हूं कि संवैधानिक पहलू के साथ साथ कोई नैतिक पहलू भी है या नहीं ?

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का कोई तो उत्तर आना चाहिये, यह बिलकुल नियम के अनुसार है, वह नियम के अनुसार जवाब दें। आप हमारे अधिकारों की रक्षा नहीं करेंगे, अध्यक्ष महोदय ?

अध्यक्ष महोदय : रक्षा तो करेंगे, भाई।

श्री मधु लिमये : फिर तो मुझे सभा त्याग करना पड़ेगा। मैं पचासों नहीं लाखों उदाहरण

दे सकता हूँ कि सम्बन्धित प्रश्न पूछे गये हैं। आप हमारे अधिकारों की रक्षा नहीं कर रहे हैं।

MR. SPEAKER : After all it is not that I prevent the Home Minister from answering. If he can answer it, that is a different matter. If he has consulted and if he is ready with the answer I am not preventing. I cannot also at the same time force him to say at this stage.

श्री मधु लिमये : वह ऐसा कहें कि सोच कर बाद में बतलायेंगे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : वह यह तो कहें कि नैतिक पहलू को ध्यान में रखा जायेगा।

SHRI RANGA (Srikakulam) : I do not know what he has said. If what he has said is within the Rules, then you will ask the Home Minister to answer.

श्री रवि राय : अध्यक्ष महोदय, मधु लिमये साहब ने जो औचित्य का सवाल उठाया है, इसके बारे में वह कहें कि सोच रहे हैं, बाद में बतलायेंगे। कुछ तो कहें। कुछ भी नहीं कह रहे हैं, आप कुछ तो जवाब दिलवाइये।

SHRI SHEO NARAIN : The Home Minister has no right to say thing about the election of a leader of a party in the Vidhan Sabha. If Shri Madhu Limaye wants, he must go to the Congress President and put this question to him.

MR. SPEAKER : The Home Minister said that he is consulting the Attorney-General about Shri Mishra's cease.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH (Nandyal): On a point of order, Sir. As you have correctly said, it is whether the Congress Party has consulted the Attorney-General. Hon. Shri Madhu Limaye has raised another point which is not at all relevant to the calling attention that is before the House. So Sir, you have correctly given your ruling that is irrelevant and Home Minister need not answer.

MR. SPEAKER : I did not say that he need not answer. *(Interruptions)*

श्री मधु लिमये : यह इर्रेलेवेन्ट कहां है? इस तरह से इनकी बातों को मैं नहीं चलने दूंगा।

SHRI P. VENKATASUBBAIAH : I want your ruling whether this is very much relevant to the supplementary that has been asked by Shri Madhu Limaye. Is it at all relevant to the point under discussion ?

SHRI S. M. BANERJEE : On the same thing I have got a point of order. The calling attention is to call the attention of the Minister of Home Affairs to the reported decision of the Congress Party to consult the Attorney-General (that is one) about the legal implications of the orders passed by Madhya Pradesh High Court in respect of Shri D. P. Mishra. So, the main charge is that the Congress Party wanted to consult the Attorney-General which they say it cannot do as a political party because the Central Government can take it up and so on The question put by my hon. friend Shri Madu Limye arising out of the m in answer and the question put by Shri Vajpayee are this : the Minister can refuse to answer the question on three grounds : if it is on public interest, or, if he does not want to say anything or he wants notice and so on. He could have asked for notice because this is a general question which has been asked, but the supplementary questions are very pertinent and very relevant, and you, as the custodian of parliamentary democracy, have to help the questioners. *(Interruptions)*. I would request you to consider this : let the Minister ask for notice or anything like that, and then we can develop a discussion on that. *(Interruptions)*

SHRI NARENDRA KUMAR SALVE (Betul) *rose*—

MR. SPEAKER : Order, order. Let me first reply to the first point of order. Shri Venkatasubbaiah asked how that question put by Shri Limye could arise: he said it is not relevant. The point is this. The main question was that

[Mr. Speaker]

it was the Congress party which was consulting the Attorney-General. This is the point which we are concerned with. Now, the Minister's reply was that it is not the Congress party but it is the Government that is consulting the Attorney-General. (*Interruptions*). Please do not disturb. After all, I do not remember all that has been said and I am not so intelligent. The point is, the Home Minister said that they are consulting the Attorney-General about the legal implications about Shri Mishra's case, the high court judgement and all that.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : What about the moral aspect, implication ?

MR. SPEAKER : That is exactly what I am coming to. Apart from the legal implications, what about the moral implications of it ? He may or may not say about it, or he may say, "I want time" and all that. But the moral implication is also connected with the legal implication. (*Interruptions*) Order, order. No running commentary please. So I cannot compel them; I can not say it is irrelevant; it is implied, namely, the moral implication. The hon. Member has mentioned moral implication. The Minister may not say about the moral implications; or he may say he cannot answer, but that is a different matter.

SHRI Y. B. CHAVAN : As you have very rightly said, moral implications are also connected with the legal implication. But when we are trying to find out what the legal implications are, without knowing the legal implications, how can I explain the moral implication ?

MR. SPEAKER : Shri Shiva Chandra Jha.

श्री मधु लिमये : इनकी नैतिकता बिल्कुल साफ है । इनके कोई मूल्य नहीं, कोई नैतिकता नहीं ।

MR. SPEAKER : Order, order. I have called Shri Shiva Chandra Jha.

SHRI PILOO MODY : I have never heard of moral implications arising out of legal implications !

SHRI RANDHIR SINGH : Moral implications follow legal implications.

श्री शिव चन्द्र झा : अध्यक्ष महोदय, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि लीगल इम्प्लीकेशन्स के साथ ही मारल इम्प्लीकेशन्स सम्बन्धित हैं, दोनों को अलग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब मैं मंत्री महोदय के सामने सीधा सवाल रखने से पूर्व आपसे दो एक बातें कहना चाहता हूँ। सन् 1946–47 में गांधी जी डेढ़ दो महीने के लिए पटना में जाकर रहे थे तो बिहार की रूलिंग पार्टी की बातें उनके सामने आई थीं। उस समय बिहार के मुख्य मंत्री श्री बाबू थे। उनके मुताल्लिक बहुत सी बातें उनके सामने आई थी। गांधी जी उन बातों पर विचार करने के बाद कंविन्स्ड हो गए थे कि श्री बाबू को मुख्य मंत्री के पद पर नहीं रहना चाहिए। तो गांधी जी की यह ख्वाहिश थी कि ऐसे आदमी को इस प्रकार के पद पर नहीं रहना चाहिए जिसके खिलाफ जनता को आपत्तियां हों। यदि किसी के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें हों तो फिर उस व्यक्ति को मुख्य मन्त्री नहीं रहना चाहिए, ऐसी उनकी ख्वाहिश थी। गांधी जी की दूसरी ख्वाहिश यह थी कि आजादी के बाद कांग्रेस को डिजाल्व कर देना चाहिए और लोक सेवक दल के रूप में बदल देना चाहिए। तो गांधी जी की उन दोनों ख्वाहिशों के विपरीत जाकर यह कांग्रेस कार्य कर रही है जिसका उदाहरण हमको अभी मध्य प्रदेश में मिल रहा है। मध्य प्रदेश की हाइकोर्ट ने श्री डी० पी० मिश्र के मुताल्लिक खिलाफ फैसला दिया है और वह फैसला अभी उसी रूप में है और यहां पर डेफेक्शन कमेटी का निर्माण हुआ है ताकि लोग डेफेक्ट करके इधर से उधर न जांय, आप मारल बातों पर विचार कर रहे हैं, इस प्रवृति पर रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आप कहते हैं कि एटार्नी जनरल की सलाह कांग्रेस पार्टी ने नहीं मांगी है बल्कि सरकार ने मांगी

है और इस सरकार के गृह मन्त्री डेफेक्शन्स पर रोक लगाने की भी कोशिश कर रहे हैं, ऐसी हालत में मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आपके लिये यह उचित है कि जब तक श्री डी० पी० मिश्र पर लगाये गये ये चार्जेज खत्म नहीं हो जाते, आप एटार्नी जेनरल से सलाह मांगें और इस प्रकार के कदम उठायें जिससे वहां की स्थिति और बिगड़े ? क्या आपका यह कार्य संविधान के अनुकूल होगा ?

SHRI Y. B. CHAVAN : I do not think we have done anything contrary to the Constitution. The other aspect of it, I have already answered.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (हापुड़) : पीछे हरियाणा में जब दल-बदलुओं को टिकट न देने का निश्चय किया गया था और इसी प्रकार से बिहार के कुछ शीर्षस्थ नेताओं पर जब इसी तरह के भ्रष्टाचार के आरोप कोर्ट के विचाराधीन थे तो उनको भी टिकट न देने का निश्चय कांग्रेस ने किया था। उससे देश में ऐसी भावना फैली थी कि कांग्रेस पार्टी और उसके बड़े-बड़े नेता राजनीति में स्वस्थ आदर्श उपस्थित कर रहे हैं। परन्तु मध्य प्रदेश में इन दोनों प्रवृत्तियों दल-बदलुओं की प्रवृत्ति और भ्रष्टाचारियों को मंत्री बनाने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने से ऐसा लगता है कि अपने बनाये हुए आदर्शों की स्वयं वही लोग हत्या कर रहे हैं जिन्होंने कुछ महीने पहले उन आदर्शों को उपस्थित किया था।

मैं जानना चाहता हूं क्या यह सत्य है कि एटार्नी जनरल की राय लेने से पहले मध्य प्रदेश के एडवोकेट जनरल, श्री चितले से वहां के राज्यपाल महोदय ने इसी सम्बन्ध में पूछा था ? क्या श्री चितले की राय इस सम्बन्ध में वही थी कि जो कि हाईकोर्ट की राय है ? इसलिए केन्द्र गृह मन्त्री को विवश होकर एटार्नी जनरल से पूछना पड़ा, इस बात में कहां तक सत्यांश है ? श्री चितले की राय क्या थी यह मैं जानना चाहता हूं और क्या विवश होकर उसके बाद एटार्नी जनरल की सलाह लेनी पड़ी ?

दूसरी बात जो मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूं वह यह कि सन् 67 के चुनावों के बाद से ही राज्यों में अस्थिरता की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है जिससे जनतन्त्र के लिए एक समस्या उपस्थित हो चली है। इन सारी बातों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए क्या माननीय गृह मन्त्री इस प्रकार का कोई निश्चय लेने जा रहे हैं कि सभी राजनीतिक दलों या उन राजनीतिक दलों को जिनका कि जनतन्त्रीय प्रणाली में विश्वास हो, एक साथ बिठाकर भविष्य के लिए कुछ इस प्रकार की परम्परायें निर्धारित करें ताकि प्रतिदिन संसद और विधान सभाओं में इस प्रकार की कठिनाइयां उपस्थित न हों ?

SHRI Y. B. CHAVAN : The hon. member has expressed his opinion about the general attitude of political parties. I do not think I need go into that aspect of it here. But as far as the allegation that we knew about the view of the Advocate-General of Madhya Pradesh and therefore we decided like that is not true. I have no information whether the Governor consulted the Advocate General or not. We have no information about his view. I am offering for the information of the House that he consulted the legal department of the Government and they advised him that the disqualification is not automatic. Even then he decided that it is much better that he should arm himself with the highest opinion he could get in the country.

SHRI NATH PAI : When Shri Chavan took us by surprise by blundering into the statement that till the legal implications are clear he cannot talk of moral implications, it was a case of being the devil's advocate. You would never have made such a statement. How *prima facie* absurd it is! Deep within you something was telling you that you are today upholding a weak case. For legal implications, he will be consulting the Atto-

[Shri Nath Pai]

ney General. May I know when he will be consulting for moral implications ? Who is the Shankaracharya whom he will be turning to ?

SHRI SHEO NARAIN : Mr. Nath Pai.

SHRI NATH PAI : I am prepared to give my humble opinion right now here.

Sir, in the first place, there was no need to consult the Attorney-General of India. There are two issues to be borne in mind. There has been a dangerous tendency on the part of the present Government. We have seen that what is meant for the country is often abused by turning it into an instrument of a particular party.

Once there was a serious allegation regarding a particular Minister in the then Government brought forward by my hon. friend. Shri Hem Barua. Instead of referring the matter promptly to the authorities what the then Prime Minister did was to ask the private opinion of a Judge of the Supreme Court, and then the retired Attorney-General of India said that the Supreme Court had been humbled and, what is worse, a Judge of the Supreme Court accepted to give an opinion at the behest of the Prime Minister of India.

Once again it is happening. Here is an individual in difficulty and the mighty Government of India thinks nothing wrong in calling the services of the Attorney-General to help him. What was it that you needed advice about ? Is not the issue very simple, very clear ? I do not want to cite article 88 and provision of article 76. It is quite clear and you have tried to sum it up. I want to ask Shri Chavan, what was in doubt, what was not clear, what needed to be enunciated, what needed to be explained and what needed to be expounded ? Here is a citizen of India Some people called him *mamooli nagarik*. He is today declared unseated by the highest judiciary of the State. What do we do in a crisis ? Many hon. Members, coming up to Shastriji, have cited the practice which they are pretending to follow. Five leaders of Bihar Congress were not given seats. Because of what were they not given seats ? No legal implications were involved, but morally they were found to be unworthy and therefore you denied them the ticket (*Interruptions*).

Why are you having different standards? You had one standard for Mr Chenna Reddy and you are having another standard for the mighty D. P. Misra. He is a very strong powerful element. He has a big say in making Prime Minister in India. So the standard that is applied in Bihar or in the Haryana or in the case of Chenna Reddy can be thrown to the wind. The very act of consulting, the very act of calling in the Attorney-General of India is a gross disrespect of the Constitution of India.

The Home Minister said that the Congress Party did not consult; it is the Government of India. Thank you for this kind mercy. We are yet spared this humiliation that the Congress did not summon the Attorney-General to the AICC and ask him 'चला बताओ भाई क्या तुम्हारी राय है।"

We are grateful for this kind mercy, that things have not come to that stage. But the issue was very clear. It is not clear that the man has been unseated and the ground given by the Judge is "guilty of corrupt practices."

AN. HON. MEMBER : No.

SHRI NATH PAI : This is the finding.

श्री विभूति मिश्र (मोतिहारी) : इनकी पार्टी के लोग बिहार में थे जिनके बारे में मशोलकर साहब विचार कर रहे हैं। तो उनको इन्होंने टिकट क्यों नहीं मना किया ?

श्री नाथ पाई : जो न्यायाधीश के निर्णय में है वही मैं जिक्र कर रहा हूं।

SHRI NATH PAI : In that case, on three grounds I want to seek clarification. First of all, will the office of the Attorney-General be available to me if I want to consult him ? Supposing tomorrow I am unseated, will Shri Chavan proclaim that in

order to find the legal implications of Shri Nath Pai being unseated he is asking the advice of the Attorney-General ? When I asked the then Prime Minister, Pandit Nehru, when he referred the case to a Judge of the Supreme Court for private opinion, whether that service of the Supreme Court Judge was available to me, he laughed at me by saying : "I do not know what the Judge of the Supreme Court will do if Shri Nath Pai writes, but I wrote and he accepted." Shri Setalvad wrote one of the finest thesis on this, that this was humiliation of Supreme Court, insult of the Supreme Court and gross impropriety. In the first place, are the services of the Attorney-General of India avaiable to citizens in the cases they claim to be in doubt ? How does the Government of India concern itself with the ambitions or the difficulties of an individual. Shri D. P. Mishra is nothing more than an individual. You have told us that he has been elected a leader. First you do one wrong morally and then to uphold that moral wrong of electing a man declared corrupt you commit a political impropriety. Shri Chavan is nodding his head in anger.

SHRI Y. B. CHAVAN : I am not angry.

SHRI NATH PAI : I am very happy it was only a disapproval: okay. Thirdly, should we not create precedents that people unseated by the courts will not be allowed to be heads of governments ? Or are we encouraging this kind of unholy tendency, whatever the courts say, so long as political purposes are furthered to hell with the courts, we shall go ahead ? Finally, in regard to defections Shri Chavan had stated: let us try to create healthy precedents. I want to know whether what has happened is a healthy precedent. I want replies to these four specific questions.

SHRI Y. B. CHAVAN : I do not know as a matter of fact, how many questions he asked. First of all, he asked me: whom are you going to consult on moral values, Sankaracharya ? I never consult Shankaracharya in these matters. My main difficulty has arisen because on this particular issue they have convemently convinced themselves that there is no legal issue involved. Well, certaintly, they are entiled to hold that view. But it is very correct that when an issue is raised, when legally there are two views on a particular matter...

SHRI NATH PAI : What is the issue ?

SHRI Y. B. CHAVAN : I did mention that the Madhya Pradesh Legal Ministry did give the view that the disqualification is not automatic. Under these circumstances it is very right for the Governor to ask for some legal advice, which is available.

श्री रवि राय . चेन्ना रेड्डी के बारे में बताइये ।

SHRI NATH PAI : Why was it not done in the case of Dr. Chenna Reddi ?

SHRI Y. B. CHAVAN : Because, Dr. Chenna Reddi himself decided to resign. So, there was no question of our taking any view in this matter. If at that time you had asked me to take the view of the Attorney-General, possibly I would have done that also. I really do not understand one thing. Why are they afraid of consulting the best legal consultant in the country ? If it is possible and if we have got the advice, what is wrong with it ? Are they afraid of the opinion of the Attorney-General ?

श्री हुकम चन्द कछवाय (उज्जैन) । हमारे बारे में राय लेंगे ?

SHRI Y. B. CHAVAN : I am afraid they are trying to put the cart before the horse. The advice of the Attorney-General on the legal implications has to be considered before a decision is taken.

SHRI NATH PAI : What about my second question ? I raised four specific questions. He has touched only the first, that according to him there is an issue and so he has taken the legal opinion. I would say that it was a tragedy that he consulted the Law Ministry, he took Shri Govinda Menon into confidence and sought his opinion. He may hold a different view and he is entitled to hold that view.

SHRI Y. B. CHAVAN : I did not say the Law Ministry of the Government of India ; I said the Law Ministry of Madhya Pradesh.

SHRI NATH PAI : What did you do on the 19th ?

SHRI Y. B. CHAVAN : On the 19th I discussed the matter with the Law Minister.

SHRI NATH PAI : Since he said in Parliament the other day that a public document before the Supreme Court cannot be placed on the Table of the House since then I am worried about him. Now, coming back to my question, what about an answer to them. He can say "No". Can he give an assurance to all future contestants that in case they lose the election or a case and they want the services of the Attorney-General, will it be made available to them ? Are we not going to make an evil out of all this ? Should we not show some semblande of political decency ?

SHRI Y. B. CHAVAN : The rules about consulting the Attorney-General are obvious Any State Gevernment or a layman can consult him provided it is not against the interests of the Central Government. Further, the Attorney-General is entitled to give his private opinion also ; nobody can come in the way. If the Government of India feel that it is a question which is likely to be raised in this House, or is likely to come up in the course of administration, it is certainly entitled to seek that opinion.

SHRI NATH PAI : How is D. P. Mishra or his election .. ..

MR. SPEAKER : This is over. I am going to the next item ..... (*Interruptions*)

11.50 hrs.

QUESTION OF THE PRIVILEGE AGAINST EDITOR OF "ORGANISER"

MR. SPEAKER : On the 18th March, 1969, Shri P. Venkatasubbaiah had sought to raise a question of privilege regarding certain comments published in the "Organiser" dated the 15th March, 1969. I had then said that I would ask the Editor to state what he had to say in the matter.

I have now received a letter dated the 21st March, 1969 from the Editor of the "Organiser" in which he has stated *inter alia* as follows :

> "I must say I am very sorry that that helf-sentence crept into the piece.
>
> We are sorr, for that comment-more so because we know Shri Venkatasubbaiah to be a distinguished leader, an accomplished Parliamentarian and, above all, a Hindu proud of his Hinduism."

In view of this, I think the matter may be dropped. I take it that the House agrees.

11.5 hrs.

BUSINESS OF THE HOUSE

MR. SPEAKER : Before we take up the other business, I would like to say that today we are sitting because the BAC decided that the Budget Demands could not be postponed. We will have to take up to the Demands on Wednesday ; so, we had only two days-Monday and Tueday-and there were the Ordinances, which we had to pass. In addition to the Ordinance, the Assam Reorganisation Bill is also there. It is supposed to be very important Members came and said that it must be finished now so that the Rajya Sabha could take it into consideration before they adjourned. So, we decided in the BAC that these Ordinances, three and four of them are there like the wakfs Ordinance and the special powers to the military, could be finished very quickly because all the Members thought that they were not very controversial and on monday afternoon we could take up the Assam Reorganisation Bill, devote the whole of Tuesday to it and finish it on that day so that on Wednesday we could take up the discussion on the Demands I hope, hon. friends will help me in finishing these things.